take to ensure availability of medicines in the dispensaries all over the country;

(c) whether it is also a fact that the beneficiaries have to wait for a number of days to get blood sugar tests done in the designated CGHS dispensaries in Delhi and outside Delhi; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps taken to tone up the infrastructure to ensure such tests on prescribed dates?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) By and large most of the listed medicines in the CGHS formulaty are presently available in the dispensaries run by the Central Government Health Scheme. However, shortages encountered occasionally are made up by resorting to local purchases from the approved local chemists. In case of emergencies, an 'Authority Slip' is issued permitting the beneficiaries to collect the medicines from the authorised local chemists directly, without making any payment. Regular meetings are held with the Stores Organisation to assess the stock position of medicines and necessary steps taken to augment supplies where needed.

(c) and (d) In some dispensaries, Blood Sugar test is done on fixed days as per previous appointment. In case of medical emergency, however, blood sugar tests are got done on priority basis. For further convenience of beneficiaries, the additional facility of referral to private diagnostic centres recognised under CGHS has also been introduced, which is available to CGHS beneficiaries on the advice of a Government Specialist, and, in case of a medical emergency, even on the advice of the CMO-Incharge of the concerned dispensary.

परिवार योजना कार्यक्रमों के लिए कंपनी क्षेत्र की सहायता लिया जाना

*140. **श्री राम जेठमलानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1997 के "दि हिन्दू" में मिनिस्टर सीक्ट कारपोरेट हेल्प इन फैमिली प्लानिंग"शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने कंपनी क्षेत्र से परिवार नियोजन कार्यक्रमों में सहयोग देने की अपील की है,

(ग) क्या सरकार ने कंपनी क्षेत्र के समक्ष कार्यान्वयन में उनके सहयोग की मांग हेतु कोई ठोस योजना रखी है, और

(घ) यदि हां, तो वह योजना क्या है और सरकार कंपनी क्षेत्र से किस रूप में सहयोग की अपेक्षा रखती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) से (घ) 11 जुलाई, 1997 से "दि हिदूं" दैनिक में प्रकाशित समाचार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा 11 जुलाई, 1997 को दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के परिसंघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में दिए गए भाषण के संदर्भ में हैं। अपने संबोधन में राज्य मंत्री ने निगमित क्षेत्र से परिवार कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने तथा अपनी क्षमता के अनुरूप स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का दायित्व संभालने का आग्रह किया है।

उद्योग से यह प्रोबोधन सरकार के इस विचार को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि आज देश के सम्मुख जनसंख्या एक नाजुक समस्या बनी हुई है और इस समस्या को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिए भारी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । इस प्रकार का व्यापक कार्यक्रम नहीं बन जाए जिसमें सरकारी, गैर-सरकारी संगठन सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। बहुत बड़ी आवश्यकताओं को देखते हुए अकेले सरकारी संसाधन और प्रयास काफी नहीं होंगे। इसलिए निगमित क्षेत्र समेत गैर सरकारी क्षेत्र को इन प्रयासों में सहभागी बनने और अपने पास उपलब्ध साधनों से परिवार कल्याण कार्यक्रम का दायित्व उठाने के लिए सहमत होना चाहिए। इस बारे में सरकार ने कोई विशिष्ट कार्यक्रम अथवा वित्तीय परिव्यय का निगमित क्षेत्र को सुझाव नहीं दिया है।

भारतीय उद्योग एंव वाणिज्य मंडल परिसंघ की परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बारे में एक समिति है और यह एक परियोजना समन्वित परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आगरा, कानपुर और मेरठ जिलों में तथा

पापुलेशन फाउंडेशन आफ इंडिया के सहयोग से दूसरी परियोजना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में चला रहा है । पंजाब हरियाणा और दिल्ली (पी एच डी) वाणिज्य और उद्योग मण्डल परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 7 परियोजनांए चला रहा है । निजी और सरकारी क्षेत्र, दोनों में अपने कामगारों और उनके परिवारों के लिए बहुत से औद्योगिक उपक्रम स्वास्थ्य सेवांए उपलब्ध करा रहें हैं जिनमें जनसंख्या नियंत्रण सेवांए भी शामिल है । सरकार का प्रयास निगमित क्षेत्र को उनके भारी संसाधनों को देखते हुए परिवार कल्याण, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण भी शामिल है, के लिए अधिक उत्तर दायित्व निभाने के लिए प्रेरित करना है ।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Generation of Nuclear Energy in the North-East

931. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have any plans/proposals to generate electricity through nuclear sources to meet the gap between demand and supply of power in the North-eastern Region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): (a) No, Sir. Government have no plans in the near future to have nuclear power generation in the North Eastern Region.

(b) does not arise.

(c) Electricity generation through nuclear power source is not planned in the North-Eastern region due to its large hydel power potential and endowment of the adjoining Eastern Region with large coal deposit.

Security arrangements in BARC

932. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received certain complaints/representations regarding security lapses or laxities, including pilferage, in Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether Government have conducted any study on security aspects of BARC in the recent past;

(d) if so, what are the details thereof and whether Government are reviewing the security arrangements.

(e) whether Government have received any representation about missing of a Security Guard namely Mr. Dineshwar Singh of BARC; and

(f) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) The security of the Bhabha Atomic Research Centre (BARC) is under constant review with a view to improving the same. A survey team of Ministry of Home Affairs had conducted detailed security inspections of the BARC in 1991 and in 1995. The recommendations of the team have been taken into consideration for upgrading the security of the establishment.

(e) and (f) Shri Dineshwar Singh is a Watchman in the Directorate of Construction, Services & Estate Management and not a Security Guard of BARC. He was reported missing on 21 June, 1996. A report was lodged with the Mahim plice station on 23 June, 1996. The case was also reported to the Missing Persons'